

ब.अ. 2022-23 और सं.अ. 2022-23 के बीच व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2022-23 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में ₹ 2,42,323 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। व्यय की मंदा, जहां अन्तर आए हैं, नीचे दर्शाई गई हैं:-

(₹ करोड़)			
	ब.अ. 2022-23	सं.अ. 2022-23	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
1 उद्योग	91266	173905	(+) 82639
2 खाद्य भंडारण और माल गोदाम	215643	289329	(+) 73686
3 पेंशन	207132	244780	(+) 37648
4 पेट्रोलियम	8290	33578	(+) 25288
5 रक्षा सेवाएं	385370	409500	(+) 24130
6 रेलवे पर पूंजी परिव्यय	137100	159100	(+) 22000
7 कृषि कार्य	122137	140651	(+) 18514
8 सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	180301	196820	(+) 16519
9 ग्रामीण रोजगार	73000	89400	(+) 16400
10 अन्य संचार सेवाएं	10285	24049	(+) 13764
11 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	55631	68654	(+) 13023
12 आवासन	12072	20990	(+) 8918
13 अन्य व्यय	2753592	2799711	(+) 46119
कुल व्यय	3944909	4187232	(+) 242323

निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई है

- 1 स्वदेशी यूरिया और यूरिया के आयात के लिए भुगतान हेतु उर्वरक (यूरिया) सब्सिडी के अंतर्गत अधिक आवश्यकताएं
- 2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए अधिक आवश्यकताएं
- 3 मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' के कार्यान्वयन, इस पर बकाया भुगतान के प्रावधान और सीजीएचएस पेंशनरों की चिकित्सा उपचार के व्यय के लिए
- 4 घरेलू एलपीजी की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत तेल विपणन वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को एक मुश्त अनुदान के प्रावधान को पूरा करने के लिए
- 5 सेना, नौसेना और वायु सेना के राजस्व व्यय की अधिक आवश्यकताओं के लिए
- 6 रेलवे के रोलिंग स्टॉक और ट्रैक नवीनीकरण के अधिक प्रावधान को पूरा करने के लिए
- 7 किसानों को रियायती दरों पर स्वदेशी/आयात किया हुआ विनियंत्रित फोसफेटिक और पोटैसिक उर्वरक की भिक्की पर पोषण आधारित सब्सिडी के अधिक आभंटन के लिए
- 8 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के विकास के प्रावधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अधिक निवेश
- 9 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिक आवश्यकता के लिए
- 10 बीएसएनएल को वर्ष 2024-15 से 2020-21 तक के लिए अनवाइबल रूरल वायर-लाइन ऑपरेशन्स के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन के अधिक प्रावधान के लिए
- 11 संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधन की कमी को पूरा करने हेतु अधिक आवश्यकता के लिए
- 12 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना के अधिक आभंटन के लिए